



न्यूज़बीफ

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, ब्रेंट क्रूड 105.79 डालर प्रति बैरल



नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड करीब 0.8 फीसदी गिरकर 105.79 डालर प्रति बैरल पर, वहीं अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड 1.5 फीसदी की गिरावट के साथ 93.14 डालर प्रति बैरल के आसपास आ गया। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की उम्मीदों ने कीमतों पर दबाव डाला है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति बेहतर होने की संभावना है। यह गिरावट आई तेज उछाल के बाद देखने को मिली, जब सऊदी अरब पर हूती हमलों के बाद तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका से कीमतें करीब 5 फीसदी तक चढ़ गई थीं। ब्रेंट क्रूड 3.4 फीसदी बढ़कर 106.60 डालर और डब्ल्यूटीआई 2.7 फीसदी बढ़कर 94.61 डालर पर बंद हुआ था। इससे पहले कच्चे तेल में कई दिनों तक गिरावट दर्ज की गई थी, जब सऊदी अरब से बेहतर आपूर्ति और अमेरिका-ईरान बातचीत की संभावनाओं ने कीमतों को 97 के स्तर तक धकेल दिया था। गिरावट की मुख्य वजह न्यूयार्क में चल रही अमेरिका-ईरान वार्ता की प्रगति है, जिसमें ईरान की ओर से होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने और अमेरिका की ओर से आर्थिक दबाव कम करने पर बात हो रही है। हालांकि, पश्चिम एशिया में तनाव (खासकर हूती हमलों का जोखिम) अभी बना हुआ है, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है। आगे कच्चे तेल की दिशा काफी हद तक अमेरिका-ईरान वार्ता के परिणाम और क्षेत्रीय भू-राजनीतिक गतिविधियों पर निर्भर करेगी।

एचडीएफसी बैंक ला रहा डिजिटल रुपया की नई सुविधा, अब पलाइंट में भी बिना इंटरनेट कर सकेगे पेमेंट



मुंबई। एचडीएफसी बैंक जल्द ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) डिजिटल रुपया के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाने वाला है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ग्राहक अब पलाइंट में बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी खरीदारी कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक इस सुविधा को अपने पाइंट-आफ-सेल (पीएसओ) डिवाइस के जरिए उपलब्ध कराएगा, जिससे यात्री उड़ान के दौरान खाने-पीने या सीट अपग्रेड जैसी सेवाओं के लिए आसानी से भुगतान कर पाएंगे। यह सुविधा केवल पलाइंट तक सीमित नहीं है। एचडीएफसी बैंक अपने डिजिटल रुपया वालेट को भीम यूपीआई के साथ इंटीग्रेट कर रहा है, जिससे ग्राहक किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड पर स्कैन कर सामान्य यूपीआई भुगतान की तरह ही डिजिटल रुपये का उपयोग कर सकते हैं। इससे व्यापारियों के लिए भी इसका उपयोग आसान हो जाएगा। बैंक डिजिटल रुपया गिफ्ट वाउचर भी तैयार कर रहा है, जो ग्राहकों के वालेट में सीधे क्रेडिट हो जाएंगे और कहीं भी यूपीआई पेमेंट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है।

टाटा मोटर्स की टिगोर को नए लुक और नाम के साथ पेश करने की तैयारी



नई दिल्ली। अपनी सब-4 मीटर सेडान टिगोर को टाटा मोटर्स एक नए नाम और नए लुक के साथ पेश करने की तैयारी में है। इस नए माडल का नाम टाटा एरिस रखने का फैसला किया है और इसकी लान्च की तारीख 25 सितंबर 2026 तक की गई है। मौजूदा टिगोर की जगह लेने वाली यह फेसलिफ्ट कार डिजाइन, इंटीरियर और फीचर्स में कई बड़े बदलावों के साथ आएगी, जिससे यह मारुति डिजायर, हुंडई आरा और होडा अमेज जैसी कारों को कड़ी टक्कर देगी। बाजार में इसकी संभावित शुरुआती कीमत करीब 6 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रहने की उम्मीद है, जबकि टाट वेरिएंट 8.5 से 9 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। डिजाइन के मामले में, एरिस को नया दियागो जैसा आधुनिक और आकर्षक लुक मिलेगा। फ्रंट में पतली एलईडी हेडलाइट्स, ग्लास ब्लैक गिल और स्पोर्ट्स बंपर नजर आएंगे, जबकि पीछे कनेक्टेड टेल लैंप और एक नया बंपर दिया जाएगा। नए अलाय स्टील और प्रेश कलर आधान्थ भी मिलने की संभावना है। इंटीरियर में दियागो जैसी नई ईशबोर्ड लेआउट, फ्री-स्टैंडिंग 10.25 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की उम्मीद है।

नईदुनिया

टीवीएस कंपनी की माडल-वाइज बिक्री में जुपिटर सबसे आगे रहा, 4,33,796 वाहन बेचे

नई दिल्ली
टीवीएस मोटर कंपनी ने अगस्त 2026 में बिक्री के मामले में मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी ने कुल 4,33,796 टू-व्हीलर्स सेल किए, जो अगस्त 2025 में हुई 3,68,862 यूनिट की बिक्री की तुलना में 17.60 फीसदी ज्यादा है। कंपनी की माडल-वाइज बिक्री में टीवीएस जुपिटर सबसे आगे रहा।

वहीं, टीवीएस आईक्यूब ने सालाना बिक्री वृद्धि के मामले में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया।

दूसरे स्थान पर टीवीएस अपाचे रही, अगस्त 2026 में 55,123 यूनिट बिक्री

अगस्त में टीवीएस जुपिटर कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला माडल रहा। इसकी कुल 1,47,450 यूनिट बिक्री। पिछले साल अगस्त में जुपिटर की 1,42,411 यूनिट बिकी थीं। इस तरह इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 3.54 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

रिपोर्ट के मुताबिक स्कूटर की मजबूत बिक्री ने इसे कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे आगे बनाए रखा। दूसरे स्थान पर टीवीएस अपाचे रही। अगस्त 2026 में इसकी 55,123 यूनिट

बिक्री, जबकि अगस्त 2025 में 45,038 यूनिट की बिक्री हुई थी। इस तरह अपाचे की बिक्री में सालाना आधार पर 22.39 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे बाइक की मांग में मजबूत वृद्धि का संकेत मिलता है। टीवीएस आईक्यूब ने बिक्री वृद्धि के मामले में सबसे तेज प्रदर्शन किया। अगस्त 2026 में इसकी 42,882 यूनिट बिक्री, जबकि पिछले साल इसी महीने में 24,434 यूनिट की बिक्री हुई थी यानी आईक्यूब की बिक्री में सालाना आधार पर 75.50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री में यह उछाल टीवीएस के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कारोबार के लिए अहम रहा। रिपोर्ट के मुताबिक टीवीएस रेडर की भी मांग बढ़ी है। अगस्त में इसकी 37,002 यूनिट बिक्री, जबकि अगस्त 2025 में 33,434 यूनिट की बिक्री हुई थी।

इसके चलते रेडर की सालाना बिक्री में 10.67 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी के अन्य माडलों की बात करें तो अगस्त 2026 में एनटार्क 125 की 28,298 यूनिट, आर्बिटर की 14,641 यूनिट, रेडियन की 14,074 यूनिट, एनटार्क 150 की 11,958 यूनिट, रोनिन की 11,679 यूनिट, स्पोर्ट की 11,615 यूनिट और जेस्ट की 11,213 यूनिट बिक्री। अपाचे आरटीएक्स/310 की 1,925 यूनिट की बिक्री हुई। वहीं, स्टार सिटी की अगस्त में कोई यूनिट नहीं बिकी। कुल मिलाकर अगस्त की बिक्री में जुपिटर ने टीवीएस के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया, जबकि आईक्यूब को तेज सालाना वृद्धि और अपाचे और रेडर की बढ़ती मांग ने कंपनी के टू-व्हीलर कारोबार में अलग-अलग सेगमेंट की मजबूत स्थिति को दिखाया।

छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी जानें कब लेना है नंबर, कब नहीं

जानें टर्नओवर की सीमा और वे परिस्थितियां जब कम कमाई पर भी लेना पड़ सकता है जीएसटी नंबर

नई दिल्ली
देश के लाखों छोटे कारोबारी, चाहे वे सड़क किनारे चाय बेचते हों, सब्जी की दुकान चलाते हों या मोहल्ले में किराना स्टोर संभालते हों, अक्सर इस उलझन में रहते हैं कि क्या उन्हें भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। यह एक आम धारणा है कि हर कारोबार शुरू करते ही जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, लेकिन ऐसा हर मामले में नहीं है। सरकार ने छोटे व्यवसायों को राहत देते हुए उनके टर्नओवर और व्यापार के प्रकार के आधार पर कुछ नियम बनाए हैं। आइए समझते हैं कि एक छोटे दुकानदार को कब जीएसटी के दायरे में आना होता है और किन खास परिस्थितियों में कम कमाई होने पर भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ सकती है।

जीएसटी के नियम मुख्य रूप से कारोबार के सालाना टर्नओवर और व्यापार के प्रकार पर निर्भर करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में अगर कोई कारोबारी सिर्फ सामान बेचता है और उसका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये से कम है, तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। हालांकि, कुछ विशेष श्रेणी वाले राज्यों में यह सीमा 20 लाख रुपये है। इसी तरह सेवाएं प्रदान करने वाले कारोबारियों के लिए सामान्य सीमा 20 लाख रुपये और कुछ राज्यों में 10 लाख रुपये तक की गई है। इसका सीधा मतलब है कि छोटी किराना दुकान, सब्जी की दुकान या चाय की दुकान चलाने वाले व्यक्ति को, जिसका टर्नओवर इन सीमाओं से नीचे है, आमतौर पर जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं होती। रेहड़ी-पट्टरी पर सामान बेचने वाले छोटे कारोबारी भी टर्नओवर की इन्हीं सीमाओं के दायरे में आते हैं। सिर्फ कम टर्नओवर होना ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन से बचने की गारंटी नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों में छोटे कारोबारी को भी जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो सकता है।

उदाहरण के तौर पर, यदि कोई दुकानदार अंतरराज्यीय (एक राज्य से दूसरे राज्य) सप्लाई करता है, ई-कामर्स प्लेटफॉर्म के जरिए आनलाइन सामान



पर्सनल फाइनेंस में एआई की राह आसान, पर रहें सावधान, एआई नहीं समझ सकता आपकी पूरी आर्थिक स्थिति

नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल अब पर्सनल फाइनेंस सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा है, जिससे निवेशकों को अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप निवेश विकल्पों की तुलना करने और शुरुआती जानकारी जुटाने में काफी मदद मिल रही है। हालांकि, वित्तीय विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एआई सिर्फ एक सहायक टूल है और निवेश से जुड़े अंतिम निर्णय लेने के लिए मानवीय विवेक और व्यक्तिगत परिस्थितियों की गहन समीक्षा बेहद अनिवार्य है। एआई टूल्स निवेशकों को उनकी आय, वित्तीय लक्ष्यों, निवेश की अवधि और जोखिम क्षमता के आधार पर एसआईपी, एफडी, शेयर और म्यूचुअल फंड जैसे विभिन्न विकल्पों की तुलना करने में मदद करते हैं। एआई निवेश से जुड़ी शुरुआती रिसर्च को तेज कर सकता है और संभावित रिटर्न, टैक्स पहलुओं व तरलता जैसे मुद्दों की तुलना में सहायक है। हालांकि, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि एआई की सलाह के आधार पर ही अंतिम निवेश का फैसला लेना उचित नहीं है। विशेषज्ञ बताते हैं कि एआई से मिलने वाले विश्लेषण की गुणवत्ता उसके माडल और उपलब्ध डेटा पर निर्भर करती है। अगर जानकारी पुरानी या गलत है, तो निष्कर्ष भी भरोसेमंद नहीं हो सकते। इसलिए, एआई के सुझावों की मानवीय समीक्षा बेहद आवश्यक है। नए निवेशकों के लिए एआई अलग-अलग निवेश विकल्पों को समझने में उपयोगी हो सकता है, जैसे एफडी को कम जोखिम वाला और शेयर बाजार को अधिक जोखिम वाला विकल्प समझना।

बेचता है, या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से जुड़े लेन-देन करता है, तो उसे अनिवार्य रूप से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसका टर्नओवर निर्धारित सीमा से कम हो। ऐसे में, यदि आप अपने कारोबार को आनलाइन ले जाने या दूसरे राज्यों में विस्तार करने की सोच रहे हैं, तो नियमों की जांच अवश्य कर लें। एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, कारोबारी की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उसे अपने कारोबार के

हिसाब से जीएसटी रिटर्न और अन्य आवश्यक जानकारी समय पर जमा करनी होती है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि भले ही किसी अवधि में बिक्री न हुई हो, फिर भी लागू रिटर्न फाइलिंग नियमों का पालन करना पड़ सकता है। छोटे कारोबारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम एक सरल विकल्प हो सकता है, बशर्ते वे इसके लिए पात्र हों। यह स्कीम टैक्स और अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाती है।

एक्सिस म्यूचुअल फंड और ग्रिप इन्वेस्ट में साझेदारी



मुंबई। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपनी डिजिटल पहुंच बढ़ाने और निवेशकों के लिए निवेश को सरल बनाने हेतु ग्रिप इन्वेस्ट के साथ साझेदारी की है। इस गठजोड़ से ग्रिप इन्वेस्ट ऐप के उपयोगकर्ता अब एक्सिस म्यूचुअल फंड की चुनिंदा इक्विटी, डेट और गोल्ड फंड योजनाओं में सीधे निवेश कर सकेंगे। यह साझेदारी एक्सिस म्यूचुअल फंड की फिनटेक कंपनियों के साथ सहयोग कर अपने डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को विस्तारित करने की रणनीति का हिस्सा है। इसका मुख्य लक्ष्य म्यूचुअल फंड निवेश को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाना है, विशेषकर डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले निवेशकों के लिए। साझेदारी की एक अहम विशेषता आटोमैटिक री-इन्वेस्टमेंट की सुविधा है। इसके तहत, निवेशक ग्रिप इन्वेस्ट पर अपने बान्ड निवेश से मिलने वाले रिटर्न को स्वचालित रूप से एक्सिस म्यूचुअल फंड की विभिन्न योजनाओं में फिर से लगा सकेंगे। यह प्रक्रिया को सरल कर अनुशासित दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देगी। एक्सिस म्यूचुअल फंड के चीफ डिजिटल ऑफिसर, बोनिफेस नोरोन्हा ने कहा कि निवेशक आसान और सहज समाधान चाहते हैं। ग्रिप इन्वेस्ट के निखिल अग्रवाल ने बताया कि इस पहल से बान्ड रिटर्न को इक्विटी, डेट और गोल्ड फंड में विविधता लाने हेतु फिर से निवेश किया जा सकता है। यह कदम एसेट मैनेजमेंट कंपनियों द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है।

फेरारी भारत में करेगी यूनिवर्सो प्रदर्शनी का आयोजन

नई दिल्ली
लज्जरी कार निर्माता कंपनी फेरारी पहली बार भारत में अपनी बहुप्रतीक्षित फेरारी यूनिवर्सो प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है। यूनिवर्सो फेरारी का पांचवां संस्करण 17 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली स्थित यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपोजे सेंटर में आयोजित किया जाएगा। यह वैश्विक आयोजन फेरारी के समृद्ध इतिहास, मोटरस्पोर्ट विरासत, तकनीकी प्रगति और भविष्य की दिशा को एक ही छत के नीचे प्रदर्शित करेगा। इससे पहले यह इटली, आस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड में सफलतापूर्वक आयोजित हो चुका है। यह प्रदर्शनी फेरारी के पुराने प्रतिष्ठित क्लासिक माडलों से लेकर वर्तमान और आगामी कारों तक को एक साथ देखने का अनूठा अवसर प्रदान करेगी। इसमें 849 टेस्टारोसा, 12सिलिंड्री, पुरोसांगुई और अमाल्फेनी स्पाइडर जैसे मौजूदा माडल के साथ कंपनी की नई एफ80 सुपरकार और पहली इलेक्ट्रिक वोइकल लूचे भी शामिल होंगी।

यह आयोजन फेरारी के पारंपरिक प्रदर्शन के साथ



भविष्य की तकनीक की झलक भी देगा। फेरारी की मोटरस्पोर्ट विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष रेसिंग एरिया भी बनाया जाएगा, जहां कंपनी की रेसिंग उपलब्धियों और प्रतिष्ठित रेसिंग कारों को करीब से देखा जा सकेगा। इस आयोजन का एक और मुख्य

आकर्षण फेरारी हाइपरसेल' होगा, जिसे एशिया में पहली बार प्रदर्शित किया जाएगा। यह फेरारी का नौकायन क्षेत्र में एक बड़ा तकनीकी प्रयास है, जिसे बिना रुके दुनिया का चक्कर लगाने के गति रिकार्ड के लिए विकसित किया गया है।

उदारीकरण के 35 साल: भारत का कार्यबल अभी भी अनौपचारिक क्यों



नई दिल्ली
भारत में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को 35 साल बीत चुके हैं, लेकिन देश के विशाल कार्यबल को औपचारिक बनाना अभी भी एक बड़ी अधूरी चुनौती बना हुआ है। 1991 के सुधारों ने औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर और विदेशी निवेश खोलकर बेशक विकास को रफ्तार दी, लेकिन यह लाखों श्रमिकों को अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक रोजगार की ओर सफलतापूर्वक नहीं ले जा पाया, जैसा कई अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में देखा गया।

वर्तमान पीएलएफएस आंकड़ों के अनुसार, भारत के लगभग 73 फीसदी गैर-कृषि श्रमिक अभी भी अनौपचारिक उद्यमों में कार्यरत हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्थिति के पीछे केवल कड़े श्रम कानून ही नहीं, बल्कि भारत की औद्योगीकरण रणनीति, सूक्ष्म और लघु उद्यमों का प्रभुत्व, कमजोर विनिर्माण वृद्धि और कोशल की कमी जैसे कई अन्य बड़े कारण भी हैं। 1993-94 में, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 50वें दौर के अनुसार, कृषि से बाहर के रोजगार का 80.3 फीसदी हिस्सा अनौपचारिक था, जिसमें अनुमानित 10.05 करोड़

1991 के सुधारों के बावजूद करोड़ों श्रमिकों को औपचारिक रोजगार में नहीं ला पाया देश

गैर-कृषि श्रमिक अनौपचारिक रोजगार में थे। इंडियन स्कूल आफ पब्लिकल इकानमी के एक अधिकारी के अनुसार उदारीकरण से पहले की नीतिगत पसंदों ने दशकों तक श्रम बाजार को आकार दिया। उन्होंने बताया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर अग्र दिया गया, और एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा (एमआरटीपी) अधिनियम के बाद उद्योगों के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया। इससे छोटे पैमाने के उद्योगों का तेजी से विकास हुआ, लेकिन इनमें ज्यादातर नौकरियां कम कुशल, कम वेतन वाली और कम रोजगार सुरक्षा वाली थीं। इसके परिणामस्वरूप, कृषि से शहरों की ओर पलायन करने वाले श्रमिकों ने इन अनौपचारिक नौकरियों को स्वीकार कर लिया, जिसका लाभ मुख्य रूप से छोटी कंपनियों को ही मिला।



कर दिया था, और बाजार आगे भी दरों में बढ़ोतरी की संभावना का आकलन कर रहे हैं। एक मजबूत डालर और अमेरिकी बान्ड की ऊंची यील्ड भी सोने पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, क्योंकि ये कारक सोने जैसे गैर-व्याज वाले निवेश का आकर्षण घटाते हैं। हाल ही में अक्टूबर सोना 1.54 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से गिरकर लगभग 1.51 लाख रुपये पर आ गया है, जबकि दिसंबर चांदी भी 2.40 लाख रुपये से ऊपर से घटकर करीब 2.34 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है।

भारतीय बाजार में पेश होगी पांच नई इलेक्ट्रिक कारें

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में जल्द ही पांच नई इलेक्ट्रिक कारें दस्तक देने वाली हैं, जो ग्राहकों को लंबी ड्राइविंग रेंज, बड़ी बैटरी पैक, आधुनिक सुविधाओं और विभिन्न जरूरतों के हिसाब से विकल्प प्रदान करेंगी।- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे वाहन निर्माता कंपनियां लगातार नए माडल पेश कर रही हैं। इनमें टाटा एरिस ईवी, टाटा सफारी ईवी, हुंडई एचईआई, महिंद्रा बीई07 और जेएसडब्ल्यू आईकार वी23 शामिल हैं, जो किफायती दैनिक उपयोग वाली कारों से लेकर प्रीमियम सात-सीटर एसयूवी तक के सेगमेंट में होंगी। टाटा मोटर्स अपनी टिगोर ईवी का नया संस्करण एरिस नाम से 25 सितंबर को लान्च कर सकती है। इसमें नए डिजाइन के हेडलैंप, बंपर और जुड़े हुए टेललैंप के साथ 19 किलोवाट-घंटा और 24 किलोवाट-घंटा बैटरी विकल्प मिल सकते हैं। वहीं, टाटा त्योहारी मौसम में अपनी प्लेगिफाइन सात-सीटर सफारी ईवी को भी पेश करेगी, जिसमें 65 किलोवाट-घंटा और 75 किलोवाट-घंटा बैटरी पैक के साथ 627 किलोमीटर तक की रेंज और आल-व्हील ड्राइव का विकल्प मिल सकता है। हुंडई इस साल दिसंबर तक अपनी सब-4 मीटर इलेक्ट्रिक कार एचईआई लान्च करेगी, जो टाटा पंच ईवी से मुकाबला करेगी। इसमें 42 किलोवाट-घंटा और 49 किलोवाट-घंटा बैटरी विकल्पों के साथ 300 किलोमीटर से अधिक की रेंज मिलेगी, साथ ही एडोप्टस जैसे फीचर्स भी होंगे। महिंद्रा अगले साल अपनी नई इलेक्ट्रिक श्रृंखला की एसयूवी बीई07 को बाजार में उतारेगी, जिसमें तीन बैटरी विकल्प (59, 70, 79 किलोवाट-घंटा) और तीन स्क्रीन वाला सेटअप होगा।